Inclusion of Washermen in the List of SC/ST in Madhya Pradesh

398. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that washermen living in three districts of Madhya Pradesh i.e. 'Rai-Sen, Sihor, and Bhopal have been placed in the category of Scheduled Castes;

(b) whether it is also a fact that Washermen living in the rest of 42 districts of Madhya Pradesh have been deprived of being declared as scheduled Castes;

(c) whether the washermen living in other districts are also proposed to be declared as Scheduled Castes; if so, by when; and

(d) whether any representations have recently been received from any washermen associations and others to consider their case of being included in the Scheduled Castes list favourably; if so, what is Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRIMATI SUMATI ORAON): (a) and (b) Dhobi community have been included in the list of Scheduled Castes only in three districts of Madhya Pradesh i.e. Bhopal, Raisen and Sehore. In other parts of the State, they have not been included in the list of Scheduled Castes.

(c) and (d) Certain representations have been received regarding inclusion of Dhobi community in the list of Scheduled Castes in whole of Madhya Pradesh. All the representations will be considered before a comprehensive proposal for amending the lists is brought before Parliament.

खाद्यान्नों के उत्पादन पर सूखे का प्रभाव

399. **श्री सीर्जा इर्शाद बेग :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सूखे के कारण कितनी कृषि भूमि प्रभावित हुई हैं;

(ख) खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) किसानों को ऋण, बीज और भूमि सुधार के रूप में किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) देश में सूखे के कारण 44.66 मिलियन हैक्टेयर सस्यगत क्षेत्र प्रभावित हुआ ।

(ख) देश के अधिकांश भागों में गम्भीर सूखा तथा पूर्वी राज्यों में बार-बार तथा लम्बी अवधि तक आई बाढ़ों के कारण खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की आशा नहीं हैं । तथापि, रबी मौसम के दौरान उत्पादन बढ़ाने के लिए एक विस्तृत नीति कार्यान्वित की जा रही है ।

(ग) सूखा राहत कार्यों के अन्तर्गत राज्यों के लिए विभिन्न मदों हेतु व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर कर दी गई है। इसमें कृषि आदानों हेतु राज-सहायता, पशु संरक्षण तथा चारा आपूर्ति के लिए सहायता तथा अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने के लिए सहायता शामिल है ।

राजस्थान और गुजरात सरकारों से सूखा राहत के लिए अभ्यावेदन

400. **श्री सीर्जा इर्शाद बेग :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उत्पन्न सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार की क्या योजनाएं

हैं और प्रत्येक राज्य को अब तक कितनी-कितनी धनराशि दी जा चुकी है ; और

(ख) क्या सरकार को राजस्थान और गुजरात राज्यों से सूखा राहत के संबंध में हाल ही में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; यदि हां, तो इस पर कब तथा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री श्याम लाल यादव) : (क) सरकार ने देश में सूखा की स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं । राज्यों को कार्यान्वियन हेतु एक कार्य योजना परिचालित की गई थी । राज्यों से प्राप्त ज्ञापनों के प्रत्युत्तर में व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर करने के अतिरिक्त चारा उत्पादन, अभिज्ञात, सिंचाई को पूरा करने तथा सब्जियों का उत्पादन जैसी मदों के लिए भी सहायता मंजूर की गई है । 1987–88 के दौरान प्रत्येक राज्य को सूखा के लिए अब तक निर्मुक्त की गई राशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । (नीचे देखिये)

(ख) गुजरात और राजस्थान सरकारों द्वारा सूखा राहत हेतु केन्द्रीय सहायता मांगने के लिए हाल ही में प्रस्तुत किए गए ज्ञापनों के प्रत्युत्तर में, जून, 1988 तक व्यय के लिए क्रमशः 262.66 करोड रुपए तथा 359.09 करोड रुपए की अधिकतम सीमा मंजूर की गई है ।

विवरण

1987–88 के दौरान सूखा हेतु राज्यों को निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं०	राज्य	निर्मुक्त की गई राशि
1.	आंन्ध्र प्रदेश	20.17
2.	असम	2.72
3.	गुजरात	155.77
4.	हरियाणा	28.47
5.	हिमाचल प्रदेश	7.24
6.	जम्मू और कश्मीर	2.50
7.	कर्नाटक	4.18
8.	केरल	25.73
9.	मध्य प्रदेश	40.01
10.	महाराष्ट्र	29.50
11.	नागालैण्ड	1.00
12.	उड़ीसा	3.03
13.	पंजाब	3.58
14.	राजस्थान	232.03
15.	तमिलनाडु	39.18
16.	उत्तर प्रदेश	25.47
	कुल	620.38

Production of Cotton Seeds

401. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the State Governments have virtually given up systematic production and distribution of pure cotton seeds;

(b) if so, what is the percentage of decline in the production of pure cotton seeds as a result thereof and the reasons for giving up its production and distribution by the State Governments;

(c) what percentage of demand of pure cotton seeds is met at a result of the decline in its production; and

(d) the steps contemplated by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE